countries are properly taken into account in all international policy decisions.

We give the highest priority to our relations with our neighbours in South Asia and to developing and strengthening the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). With the successful conclusion of two rounds of talks on Preferential Trade Arrangements in South Asia, SAARC has now embraced the goal of establishing a Free Trade Area in South Asia (SAFTA) by the year 2001. Discussions have also commenced on promoting cooperation in the field of investment.

India is also Full Dialogue Partner of Association of South East Asian Nations (ASEAN) and is a participant of ASEAN Regional Forum (ARF). Through participation in these multi-laternal fora we aim at establishing a stable and peaceful environment leading to socio-economic progress of all the people of the region.

भारत-पाक सचिव स्तर की तीसरे दौर की वार्ता में चर्चा किए गए मुद्दे

163. **श्री ईश दत्त यादव**:
श्री रामगोपाल यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत-पाक सचिव स्तर की तीसरे दौर की वार्ता सितम्बर के दूसरे सप्ताह में नई दिल्ली में हुई थी,

(ख) यदि हां, तो उक्त वार्ता में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनका ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या उक्त चर्चा में कश्मीर मुद्दा भी उठाया गया था,

(घ) यदि हां, तो कश्मीर के संबंध में पाकिस्तान का क्या रूख रहा है, और

(ङ) चर्चा का क्या परिणाम निकला है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी)ः (क) से (ङ) भारत और पाकिस्तान के बीच पुनः शुरू हुई विदेशी सचिव स्तर की तीसरे दौर की बातचीत 15 से 18 सितम्बर, 1997 तक नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। बातचीत का यह दौर दोनों पक्षों के इस इस निर्णय के बाद आस्थगित हो गया कि परस्पर सुविधाजनक तारिखों को इस पुनः संयोजित किया जाएगा।

जून, 1997 में इस्लामाबाद में विदेश सचिवों को बैठक में आठ विषय तय किए गए अर्थात (क) शान्ति और सुरक्षा, तथा विश्वासोत्पादक उपाय, (ख) जम्मू तथा कश्मीर, (ग) सियाचीन, (घ) तुलबुल नौवहन परियोजना, (ङ) सिर क्रिक, (च) आतंकवाद और दवाईयों का गैर-कानूनी व्यापार, (छ) आर्थिक और वाणिज्यिक सहयोग, (ज) दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान-प्रदान के संवर्धन के लिए बातचीत। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि एक एकीकृत पद्धति में इन मुद्दों के समाधान के लिए एक तंत्र की स्थापना की जायेगी और दोनों देशों के विदेश सचिव शान्ति तता सुरक्षा सहित विश्वासोत्पादक उपायों एंव जम्मू और कश्मीर मसलों का सीधा समाधान निकालेंगे, और अन्य तय विषयों पर बातचीत का समन्वय करेंगे तथा उसकी निगरानी करेंगे। तीसरे दौर की बातचीत वार्ता के इन तौर तरीकों पर केन्द्रित रही।

बातचीत के दौरान हमने पाकिस्तान को साफतौर पर और स्पष्ट रूप से जम्मू तथा कश्मीर के संबंध में अपनी स्थिति दोहराई है हमने जम्मू तथा कश्मीर में सीमा पार से आंतकवाद को पाकिस्तान का समर्थन तथा प्रोत्साहन, और इस प्रकार की प्रतिकुल गतिविधियों को पूर्णतः समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में भी अपनी गम्भीर चिन्ता से अवगत करा दिया है। इस बात पर भी बल दिया गया है कि नियंत्रण रेखा पर सीमावर्ती क्षेत्रों में और जम्मू तथा कश्मीर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की अकारण गोलाबीरी बनद होनी चाहिए जिसकी वजह से निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं।

बातचीत के दौरान हमने विश्वास, मैंत्री तथा सहयोग के संबंध स्थापित करने, तथा आर्थिक, व्यापार, सांस्कृतिक, दोनों देशों के लोगों के बीच क्रियाकलाप और अन्य कार्यात्मक क्षेत्रों में व्यापक संबंध विकसित करने की अपनी इच्छा दोहराई है।

पासपोर्ट जारी करने से संबंधित लोग शिकायतों पर कार्यावाही

164. **श्री नागमणि**:
चौधरी हरमोहन सिंह यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पासपोर्ट जारी होने संबंधी लोक शिकायतों पर कोई संतोषजनक कार्यावीह नहीं की जाती है,

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यावीह की गई है, और

(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान किसी अधिकारी को शिकायतों का समाधान करने में असफल रहने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया है और सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्याही का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) जी, नहीं।

(ग) सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. मंत्रालय में संयुक्त सचिव (सी पी वी) और मुख्य पासपोर्ट अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन एक लोग शिकायत कक्ष की स्थापना की गई है। इस सैल में समस्त भारत में पासपोर्ट जारी करने से सम्बध शिकायतों की निगरानी के लिए दो जन सम्पर्क अधिकारियों को भी तैनात किया गया है। पत्रों और पैसों के रूप में भी शिकायतें प्राप्त होती है और उस पर उपयुक्त कार्यवाई की जाती है। चूककर्ता अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा जाता है। संयुक्त सचिव (लोक शिकायत के) के कार्यालय में प्राप्त प्रत्येक शिकायत याचिका को भारत भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाद द्वारा दिए गए संशोधन प्रारूप के अनुसार निपटाया जाता है।

2. सभी पासपोर्ट अधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए हैं कि एक तालाबंद शिकायत पेटी स्वागत कक्ष में रखा जाए और उसे प्रत्येक दिवस की समाप्ति पर खोला जाए।

3. प्रत्येक पासपोर्ट अधिकारी को यह अनुदेश दिए गए हैं कि वे राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और अन्य स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के स्थानीय संस्करण शिकायती कालमों पर नियमित रूप से नजर रखें और उन शिकायतों पर शीघ्र कर्रवाई शुरु करें।

4. इस बात के स्पष्ट अनिदेश दिए गए हैं कि प्रत्येक पासपोर्ट अधिकारी की पहुंच लोगों तक बनी रहनी चाहिए विशेष तौर पर तब, जबकि कोई आवेदक एक से अधिक बार पासपोर्ट कार्यालय का चक्कर लगा चुका हो और उसे कोई संतोषजनक उत्तर न मिला हो।

5. बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई में टेली-इंक्वायरी प्रणाली आरंभ हो गई है जिससे कि आवेदन टेलिफोन करके अपने आवेदन-पत्रों की स्थिति के बारे में कप्यूटरीकृत उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

6. पासपोर्ट जारी करने के लिए क्रियाविधियों और अपेक्षाओं के विवरण दर्शाने वाली एक सूचना पुस्तिका, तैयार की गई है और यह प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है।

(घ) ऊपर उल्लिखत उपायों के आलावा कर्मचारियों को अधिक जिम्मेदार और जबावदेह बनाने के लिए कार्रवाई की गई है। पासपोर्ट कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है और जहां कहीं शिकायत प्राप्त होती है वहां अधिकारियों को स्पष्टीकरण के लिए बुलाया जाता है।

Development of long range missiles jointly by Russia, China and Iran

165. SHRI LAKKHIRAM AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state: (a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem "Russia, China working closely with Iran", which appeared in the Hindustan Times, dated 11th September, 1997;

(b) if so, whether it is a fact that Russia and China are working closely with Iran in building long-range nuclear missiles; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALIM IQBAL SHERWANI): (a) Yes Sir.

(b) and (c) The news report is based on a "Isreaeli intelligence report". During the recent visit of the Chinese President Jiang Zemn to the USA, China gave an undertaking to withhold all further nuclear cooperation with Iran. On 9 July, 1997, a spokesman of the Russia Foreign Ministry stated that Russia did not supply any ballistic missile related components to Iran and denied having any cooperation with Iran in the missile sphere which would be in contradiction to the provisions of the Missile Technology Control Regime (MTCR). These developments are monitored regularly by the Government.

US High Tech for Space War

166. SHRI LAKKHIRAM AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state: (a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem "US going high tech for space war" which appeared in The Hindustan Times, dated 3rd September, 1997;

(b) if so, whether it is a fact that United States is getting ready for a real space war shooting down enemy satellites in space before they take pictures or rain down missiles in war;

(c) if so, the details thereof; and